Reconstitution of the Indian Jute Development Council

2820. SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news report regarding formation of the Indian Jute Development Council which appeared in the Indian Express dated the 16th November, 1992;

(b) whether Government have recently reconstituted the Indian Jute Development Council, and if so the name and brief back-ground of each member nominated on the council-alongwith the guidelines in this regard and details of the tenure and function of the council; and

(c) whether there is any provision for setting up of the Indian Cotton Textile Development Promotion Council and if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir. A copy of the Resolution dated 14th September, 1992 containing the composition and details regarding tenure and functions of the reconstituted Indian Jute Development Council is given in the Annexure [*See* Appendix CLXV, Annexure No. 44] Names of the Members of the Council nominated in pursuance of the said Resolution are indicated in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation letter dated 14th September, 1992 read with the subsequent letter dated 27.11.92 (copies given in the Annexures [*See* Appendix CLXV, Annexures Nos. 45 and 46]

(c) No. Sir.

भू-क्षरण

2821. **श्री राम नरेश यादव:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान मुख्य रूप से "सागर द्वीप" के आस-पास बड़ी तेजी से हो रहे भू-क्षरण की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या "सागर द्वीप" जैसे अन्य छोटे-छोटे द्वीपों के निकट कई स्थानों पर भू-क्षरण का खतरा पैदा हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त द्वीपों को समुद्र में जलमग्न होने से बचाने के लिए सरकार द्वारा किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) और (ख) तटरेखा के साथ साथ कटाव होना एक प्राकृतिक घटना है। समुद्रवर्ती राज्यों द्वारा बंगाल की खाड़ी में तटरेखा के साथ-साथ छिटपुट कटावों की सूचना दी गयी है। सागर द्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में और दीघा तट के निकट गंभीर कटाव की सूचना प्राप्त हुई है।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने अब दीघा और सागर द्वीप में तटरेखा को सुरक्षा प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने सुन्दरवन और 24 परगना और मिदनापुर जिलों में तटीय पहुंचों के तटों और ज्वार नदमुखीय सुरक्षा के लिए लगभग 330 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की एक स्कीम की रूपरेखा तैयार की है। इस स्कीम में 180 किलोमीटर लम्बाई तक समुद्र की दीवारों के निर्माण की परिकल्पना की गयी है। जांच के पश्चात् राज्य सरकार को केन्द्रीय जल आयोग द्वारा प्रत्येक स्थल के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की सलाह दी गयी है जिससे उनके निष्पादन की प्राथमिकताएं निर्धारित करने के साथ-साथ उनकी तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता भी स्थापित की जा सके।

Upliftment of Fishermen

2822. SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have formulated a number of schemes for the

benefit and upliftment of fishermen in the country;

(b) if so, the details thereof alongwith achievements of each such centrally sponsored scheme during the Seventh Plan;

(c) the details of scheme included in Eighth Plan for the uplift of fishermen along with financial out-lays and state wise coverage of beneficiaries in general and for Maharashtra State in particular; and

(d) what steps are proposed for modernisation/upgadation of traditional fishing for better returns to fishermen during the Eighth Plan?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN) : (a) Yes, Sir.

(b) The schemes and achievements during the 7th Plan are given below:

Scheme	Achievement
Motorisation of Traditional Craft	4,776 craft motorised and central subsidy of Rs. 167.83 lakh released for the purpose.
Introduction of Beach Landing Craft	202 Beach Landing Craft introduced and Rs. 111.08 lakh released as central assistance as subsidy.
Group Accident Insurance for Active Fishermen	About 8.5 lakh fishermen per annum insured and central assistance of Rs. 139.46 lakh released as share of premium for the plan period.
Development of Model Fishermen Villages	18 villages sanctioned and Rs. 265.78 lakh released as central subsidy for the purpose.

(c) and (d) Schemes included in the 8th Plan are as below:

Scheme	Outlay for 8th Plan
Motorisation of Traditional Craft	1000
Introduction of Plywood/FRP Craft	200
Re-imbursement of Excise Duty on HSD Oil by mechanised vessels below 20 m length	5000
Community Managed Artificial Reefs and Mariculture	500
Enforcement of Marine Fishing Regulations Act by States	3000
Group Accident Insurance	200
Establishment of Model Villages	2000
Savings-cum-Relief	2000

No state-wise allocation has been done. Sanction of funds to states is made, as and when proposals are received from the states.

किसानों के लिये लाभकारी मूल्य

2823. **चौधरी हरमोहन सिंह**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा किसानों को उनकी कृषि उपज के लिये लाभकारी मूल्य दिलाने के लिये क्या प्रयास किये गये है और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किये गये थे; और

(ग) यदि हां, तो वे लक्ष्य क्या हैं और लक्ष्यों की प्राप्ति कहां तक हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली राम चन्द्रन): (क) किसानों को उनके उत्पादन का अच्छा मूल्य दिलाना सुनिश्चित करने की दृष्टि से सरकार ने हाल ही में फसलों के उत्पादन की लागत का आकलन करने की प्रणाली में संशोधन किया है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्यों के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण विचारणीय पहलू है। संशोधित परिकल्पनाएं हैं—(1) सांविधिक न्यूनतम मजदूरी दर या वास्तविक मजदूरी दर पर, जो उच्चतर हो, मजदूरी का मूल्यांकन, (2) कुल लागत के 10 प्रतिशत की लागत की एक मद के रूप में प्रबंधकीय-निवेश के रूप में मूल्यांकन और (3) आदानों के मूल्य में प्रत्याशित से अधिक वृद्धि होने पर बुवाई के मौसम से पहले घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यों का समायोजन।

(ख) और (ग) न्यूनतम समर्थन मूल्यों के बारे